भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2005
जिसका उत्तर मंगलवार 14 मार्च, 2017 को दिया जाना है

ऑटो क्षेत्र का उत्पादन और बिक्री

2005. श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान ऑटो क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री की वृद्धि दर बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऑटो और ऑटो कलपुर्जे क्षेत्र के निर्यात और आयात की वृद्धि दर कितनी है;

(घ) क्या विमुद्रीकरण का ऑटो क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या विभिन्न पहल की जा रही हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन(सियाम) ने सूचित किया है कि पिछले कुछ वर्षों में वाहनों के अधिकतर सेग्मेंटों में उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत है:

वित्त वर्ष	वृद्धि दर	
	उत्पादन	बिक्री
2013-14	4.13%	3.54%
2014-15	8.64%	7.06%
2015-16	2.58%	3.78%
2016-17 (अप्रैल, 16 - जनवरी, 17)	6.05%	8.00%

(ग): ऑटो और ऑटो कलपुर्जों के निर्यात एवं आयात की वृद्धि दर निम्नलिखित है:

<u>ऑटो सेक्टर</u>

वित्त वर्ष	निर्यात	आयात
2013-14	8.1%	-51.7%
2014-15	11.5%	1.6%
2015-16	-0.5%	0.9%

(स्रोत: सियाम)

<u>ऑटो कलपुर्जा सेक्टर</u>

वित्त वर्ष	निर्यात	आयात
2013-14	16.7%	3.6%
2014-15	11.4%	7.5%
2015-16	3.5%	9.3%

(स्रोत: एक्मा)

(घ) और (ङ): भारी उद्योग विभाग ने ऑटो सेक्टर पर विमुद्रीकरण के असर का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(च): भारत सरकार ऑटोमोटिव उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ऑटो उद्योग के साथ मिलकर कई पहलों पर कार्य कर रही है। कुछ की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

i) ऑटोमोटिव उद्योग को अर्थवयवस्था का 'सूर्योदय सेक्टर' माना जाता है और उद्योग के प्रति सरकार की यह नीति रही है कि व्यापार मार्ग के बनिस्बत निवेश मार्ग के जरिए सभी वैश्विक कंपनियों को बाजार की पहुंच उपलब्ध कराई जाए।

ii) ऑटो नीति 2002, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 की शुरूआत करके सरकार ने उद्योग के लिए समर्पित नीति के माध्यम से उद्योग को सहायता दी है।

iii) भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण की एक नई (फेम-इंडिया) स्कीम शुरू की है। देश में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पैठ बढ़ाने में मदद के लिए यह स्कीम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन विनिर्माताओं को लाभ उपलब्ध कराती है।

iv) ऑटोमोटिव उद्योग की पहचान एक चैम्पियन सेक्टर के रूप में की गई है तथा सरकार प्रोत्साहन, ऋण की उपलब्धता, कम लागत की विद्युत, अवसंरचना, अनुसंधान एंव विकास, प्रौद्योगिकी संयोजनों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेपों तथा उद्योग के विकास के लिए व्यापार परक्रामण के दौरान ध्यान रखने का कार्य कर रही है।

v) ऑटोमोटिव उद्योग ने उद्योग हेतु 20 टैरिफ शीर्षों को संवेदनशील मदों के तौर पर अभिज्ञात किया है जिन्हें अधिकतर व्यापार करारों में भारत की नकारात्मक सूची में डाल दिया गया है।

vi) ऑटोमोबाइल विनिर्माता वाहन निर्यातों पर 2% मैकनाइज निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (एमईआईएस) का लाभ प्राप्त करते हैं।